



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2012/फाल्गुन 3, 1933

No. 53]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2012/PHALGUNA 3, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2012

विषय : यूरोपीय संघ से बल्क औषधि सेफाइड्रोक्सिल मोनोहाइड्रेट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करने के संबंध में।

सं. 14/8/2011—डीजीएडी.—यतः मै. ल्यूपिन लि., मुंबई (जिन्हें एतदपश्चात् आवेदक कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) और सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें यूरोपीय संघ (जिसे एतदपश्चात् सम्बद्ध क्षेत्र” कहा गया है) के सदस्य देशों के मूल के या वहां से निर्यातित बल्क औषधि सेफाइड्रोक्सिल मोनोहाइड्रेट (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है और प्राधिकारी से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

और यतः प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध क्षेत्र से संबद्ध वस्तु के पाटन; घरेलू उद्योग को क्षति; और पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को मौजूद होने के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य उपलब्ध हैं और इसलिए प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार एतद्वारा संबद्ध क्षेत्र से संबद्ध वस्तु के कथित पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की जांच करने के लिए पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का पता लगाया जा सके और ऐसे पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाएगा तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद यू.एस.पी. तथा अन्य फार्माकोपियल ग्रेडों तथा औषधि के लवण यदि कोई हों, सहित सभी किस्म के बल्क इग सेफाइड्रोक्सिल मोनोहाइड्रेट हैं। सेफाइड्रोक्सिल मोनोहाइड्रेट एक सफेद से पीला-सफेद क्रिस्टल वाला पाउडर होता है। यह जल में धुलनशील है और अम्ल स्थायी है। बल्क इग सेफाइड्रोक्सिल मोनोहाइड्रेट भेषज नुस्खों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त एक सक्रिय भेषज अवयव है। बल्क इग का प्रयोग नुस्खों के विनिर्माण में होता है जो चिकित्सक द्वारा निर्देशित किए जाने पर भरीजों द्वारा लिए जाते हैं।

500 मि. ग्रा. से 1000 मि. ग्रा. तक की एकल खुराक प्रतिदिन एक खुराक या दो खुराक के रूप में उपलब्ध है। यह सिरप के रूप में भी उपलब्ध है। इस औषधि को मौखिक रूप से भली भांति लिया जा सकता है। बल्कि इग सेफाड्रोक्सिल मोनोहाइड्रेट मौखिक सेफालोस्पोरिन्स के समूह के अंतर्गत आता है। सेफालोस्पोरिन्स सामान्यतः व्यापक स्पेक्ट्रम जीवाणुवीय एजेंट होते हैं जिनमें जीवाणुवीय कोशिका वॉल सिन्थेसिस होती है। इसका उपयोग मूत्र मार्ग के संक्रमण और त्वचा के संक्रमण में भी होता है। बल्कि इग सेफाड्रोक्सिल मोनोहाइड्रेट को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय शीर्ष 29, उपशीर्ष सं. 29420011 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

घरेलू उद्योग की स्थिति

यह आवेदन मै. ल्यूपिन लि., मुंबई द्वारा दायर किया गया है और मै. अरविन्दो फार्मा लि., हैदराबाद द्वारा समर्पित है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर ये दोनों उत्पादक इस समय भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक हैं। इसके अलावा, रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी ने पता लगाया है कि (क) आवेदक का उत्पादन जांच अवधि (पी ओ आई) के दौरान भारतीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा बनता है; (ख) आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादक का घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान उत्पाद के कुल उत्पादन में 50% से अधिक हिस्सा बनता है; और (ग) आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर किया गया है।

प्राधिकारी ने उपर्युक्त की जांच करने के बाद यह निर्धारित किया है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं।

समान वस्तु

आवेदक ने दावा किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित और यूरोपीय संघ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पादों में भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण वितरण और विपणन, टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों आदि की दृष्टि से तुलनीय विशेषताएं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं, अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से संबद्ध क्षेत्र से आयातित वस्तु से तुलनीय है। घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुएं यूरोपीय संघ के सदस्य देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु हैं। प्राधिकारी आवेदक के दावे को प्रथमदृष्टया स्वीकार करते हैं और इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर संबद्ध क्षेत्र से आयातित संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

सामान्य मूल्य

प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने संबद्ध क्षेत्र में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का दावा उस कीमत के आधार पर किया है जिस पर संबद्ध क्षेत्र के सदस्य संबद्ध देशों में से एक के

निर्यातक ने किसी तीसरे देश को संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति की है, इसमें मालभाड़ा और बीमा के लिए समायोजन किया गया है।

निर्यात कीमत

संबद्ध क्षेत्र से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का निर्धारण द्वितीयक स्रोतों से संग्रहित सौदावार आयात आंकड़ों पर विचार करते हुए किया गया है। कारखाना द्वारा निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए निर्यातक देशों में समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन और पत्तन व्ययों पर विचार किया गया है।

पाटन मार्जिन

सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वारा स्तर पर की गई है जिससे संबद्ध देशों के संबंध में भारी पाटन मार्जिन का पता चलता है। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध क्षेत्र के सदस्य देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वारा निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध वस्तुओं का संबद्ध क्षेत्र के सदस्य देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

आवेदक ने वास्तविक क्षति से संबंधित विभिन्न मापदंडों संबंधी सूचना प्रस्तुत की है जिसके विश्लेषण से पता चलता है कि संबद्ध क्षेत्र आयातों का कुल मांग में मोटे तौर पर लगभग 40% का हिस्सा बना रहा है जबकि लाभप्रदता, निर्याजित पूँजी पर आय और नकद लाभ की दृष्टि से घरेलू उद्योग के निष्पादन में विकृति आई है। कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री का स्तर काफी अधिक है। इस प्रकार घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। विभिन्न आर्थिक मापदंडों के विश्लेषण से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध क्षेत्र से पाटित आयातों से वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है।

पाटनरोधी जांच की शुरूआत

पूछोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और उसके प्रभाव की जांच करने के लिए पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

जांच अवधि

जांच के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तावित जांच अवधि (पी ओ आई) 1 अप्रैल, 2010 से 31 दिसंबर, 2010 (9 महीने) है। तथापि, प्राधिकारी ने 1 अप्रैल, 2010 से 30 सितंबर, 2011 की जांच अवधि तय की है। क्षति अवधि में वित्त वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 तथा जांच अवधि शामिल है।

सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध क्षेत्र के सदस्य देशों के निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, इस जांच से संबंधित समझे जाने वाले भारत के आयातक/प्रयोक्ता/एसोसिएशनों और घरेलू उद्योग को विहित ढंग और तरीके से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग-अलग

पत्र लिखे जा रहे हैं ताकि वे निम्नलिखित पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत करा सकें :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
 पाठ्यनारोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
 भारत सरकार,
 उद्योग भवन,
 कमरा नं. 240,
 नई दिल्ली-110 011

संबंधित नियमावली के नियम 6(5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच के अधीन वस्तु के औद्योगिक प्रयोक्ताओं और ऐसे उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों जो पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं, को भी सूचना प्रस्तुत करने का अवसर दे रहे हैं। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकता है।

समय सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की तारीख से 40 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित उल्लिखित पते पर लिखित रूप में प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यह नोट किया जाए कि निर्धारित समय सीमा को बढ़ाने के लिए किसी भी अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों के लिए प्राधिकारी को प्रदत्त किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है और यदि सूचना देने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश नहीं किया जाता है तो इस बात के कारणों संबंधी विवरण प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना देने से मना करता है या अन्यथा तर्कसंगत अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में काफी बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली एक फाइल रखते हैं। कोई भी पक्षकार यदि चाहे तो उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2012

Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of bulk drug Cefadroxil Monohydrate from the European Union—reg.

No. 14/8/2011-DGAD.—Whereas M/s Lupin Limited, Mumbai (herein after referred to as the applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Rules or the AD Rules), alleging dumping of bulk drug Cefadroxil Monohydrate (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from the member countries of the European Union (hereinafter referred to as “subject Territory”) and requested the Authority for initiation of anti dumping investigation for levy of anti dumping duties on the subject goods.

And whereas, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods from the subject Territory; injury to the domestic industry; and causal link between dumping and the injury exists, and, therefore, hereby, initiates an anti dumping investigation into the alleged dumping of the subject goods from the subject Territory, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the Anti Dumping Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of anti dumping duty which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The product under consideration in the present investigation is bulk drug Cefadroxil Monohydrate of all forms including USP and other Pharmacopeial grades, and salts of the drug, if any. Cefadroxil Monohydrate is a white to yellowish-white crystalline powder. It is soluble in water and is acid-stable. Bulk drug Cefadroxil Monohydrate is

549 a 6/12-2

an active pharmaceutical ingredient used for the manufacturing of pharmaceutical formulations. This bulk drug is used to manufacture formulations, which are consumed by the patients on the prescription of the doctors. Single doses of 500 mg and 1000 mg are available as single dose or double dose per day. It is also available in the form of syrup. The drug is well absorbed orally. Bulk drug Cefadroxil Monohydrate falls under the group Oral Cephalosporins. Cephalosporins, in general, are broad spectrum bactericidal agents which inhibit bacterial cell wall synthesis. It is also used for urinary tract infections and skin infections. Bulk drug Cefadroxil Monohydrate is classified under Chapter Heading 29, Sub-heading No. 29420011 under the Customs Tariff Act, 1975. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

DOMESTIC INDUSTRY STANDING

The application has been filed by M/s Lupin Limited, Mumbai, and supported by M/s Aurobindo Pharma Ltd., Hyderabad. Based on the information on record, these two producers are the only producers of the subject goods in India at present. Further, based on the information on record, the Authority has ascertained that (a) production of the applicant constitutes a major proportion in Indian production during the period of investigation (POI); (b) the domestic producer expressly supporting the application account for more than 50 per cent of the total production of the like product produced by the domestic industry; and (c) the application has been made by or on behalf of the domestic industry.

The Authority, after examining the above, determines that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2 of the Anti Dumping Rules, and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

COUNTRY INVOLVED

The countries involved in the present investigation are the member countries of the European Union.

LIKE ARTICLE

The applicant has claimed that there are no known differences in the subject goods produced by the petitioner and exported from the European Union. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, tariff classification, etc. The goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from the

subject Territory in terms of essential product properties. The goods offered by the domestic industry are like article to the goods imported from the member countries of the European Union. The Authority, *prima facie*, accepts the claim of the applicant and, therefore, for the purpose of present investigation, subject goods produced by the applicant are being treated as “like article” to the subject goods imported from subject Territory within the meaning of the Anti Dumping Rules.

NORMAL VALUE

The Authority notes that the applicant has claimed normal value of the subject goods in the subject Territory based on the price at which the exporter from one of the member subject countries of the subject Territory supplied the subject goods to a third country, after making adjustment on account of freight and insurance.

EXPORT PRICE

Export price of the subject goods from the subject Territory has been determined by considering transaction-wise import data collected from Secondary Sources. Adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, and port expenses in the exporting countries to arrive at ex-factory export price.

DUMPING MARGIN

Normal value and export price have been compared at ex-factory level, which shows significant dumping margin in respect of the subject countries. There is sufficient *prima facie* evidence that the normal value of the subject goods in the member countries of the subject Territory is significantly higher than the ex-factory export price, indicating, *prima facie*, that the subject goods are being dumped into the Indian market by exporters from the member countries of the subject Territory.

INJURY AND CAUSAL LINK

The applicant has furnished information on various parameters relating to material injury, analysis of which shows that the imports from the subject Territory have broadly maintained their share at about 40% of the total demand whereas the performance of the domestic industry has deteriorated in terms of profitability, return on capital employed and cash profit. Level of price undercutting and underselling is significant. The domestic industry has, thus, suffered material injury. Analysis of the various economic parameters shows, *prima facie*, that domestic industry has suffered material injury from dumped imports from the subject Territory.

5449612-3

INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS

The Authority, in view of the foregoing, initiates anti-dumping investigation into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the member countries of the European Union.

PERIOD OF INVESTIGATION

The period of investigation (POI) proposed by the applicant for the investigation is from 1st April, 2010 to 31st December, 2010 (9 months). However, the Authority has fixed the period of investigation from 1st April, 2010 to 30th September, 2011. Injury period includes the financial years 2007-2008, 2008-2009 and 2009-2010 and the period of investigation.

SUBMISSION OF INFORMATION

The exporters in the member countries of the subject Territory, their Governments through their Embassy in India, importers/users/Associations in India known to be concerned with this investigation and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Government of India,
Udyog Bhavan,
Room No. 240,
New Delhi – 110011.

As per Rule 6(5) of the Rules supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation and to representative consumer organizations, who can furnish information relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

TIME LIMIT

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the

date of the Initiation Notification. It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS

In terms of Rule 6(7) of the Rules, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reasons thereof, is required to be provided to the Authority. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Designated Authority may record findings on the basis of the facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

In terms of Rule 6(7) of the Rules, the Designated Authority maintains a public file containing the non-confidential version of the evidence submitted by the interested parties. Any interested party may inspect the public file, if so desired.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority